मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

435 श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने के संबंध में सरकार ने क्या नीति बनाई है ;

(ख) इस कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले को आबंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उनके लिए आबंटित धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस योजना द्वारा लाभान्वित/लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण रोजगार विभाग में राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) मध्य प्रदेश सरकार केन्द्रीय ग्रामीण, स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है । कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा जारी की गई मार्ग-दर्शिकाओं के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को लागत की 80% सबसिडी मुहैया कराने की व्यवस्था है । मध्य प्रदेश सरकार परिवारों की गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए स्वच्छता दुकानें भी लगा रही है । सरकार द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्य घटक भी कार्यान्वित किए जाते हैं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा जिलावार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं । तथापि, मध्य प्रदेश सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई/आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं :—

(लाख रुपये में)

	आबंटित केन्द्रीय अंश	रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश	राज्य अंश
1991-92	242.64	शून्य*	80.00
1992-93	122.85	127.85	150.00
1993-94	134.16	187.28	250.00
1994-95	368.00	184.00	232.00

*योजना के अनुमोदन के अभाव में निधियां रिलीज नहीं की जा सकीं ।

(ग) बजट में दी गई निधियों के अनुसार राज्यों के लिए लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं । लक्ष्यों का राज्यवार निर्धारण राज्य सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

(घ) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत कवर की गई जनसंख्या 508.423 लाख की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से 68.0 लाख अथवा 13.37% है । भावी कवरेज केन्द्रीय और राज्य बजटों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों की सीमा पर निर्भर करती है ।

Second stream of JRY

436. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to launch a second stream of Jawahar Rozgar Yojana (JRY) in 120 most backward districts in the country;